साइबर अटैक से पूरी तरह से महफूज होगा एनसीआर का पहला ग्रीन डाटा सेंटर

आशुतोष गुप्ता, जागरण

30 हजार वर्गफीट में बनाया जाएगा 5 मंजिल का डाटा सेंटर

200 हाइ-डेंसिटी रैक हर फ्लोर पर बनाई जाएंगी

सीईएल में बनाने वाला डाटा सेंटर ● जागरण

साहिबाबाद : उत्तर प्रदेश के साथ ही एनसीआर के पहले ग्रीन डाटा सेंटर में देशवासियों का डाटा साइबर अटैक से पूरी तरह सुरक्षित होगा। मेक-इन-इंडिया क्लाउड और पीपीपी माडल पर तैयार किए जा रहे इस डाटा सेंटर में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 30 हजार वर्ग फीट में बनने वाले पांच मंजिल के इस डाटा सेंटर के हर फ्लोर पर 200 हाइ-डेंसिटी रैक हर फ्लोर बनाए जाएंगे। वहीं इसका डिजास्टर रिकवरी सेंटर दूसरे शहर में बनाया जाएगा, ताकि किसी तरह की तकनीकी खामी आने पर उसे आसानी से रिकवर किया जा सके। उपभोक्ता इसमें सुरक्षित डाटा को अपलोड या डाउनलोड कर सकेंगे। क्लाउड भारतीय होने के कारण वहां स्टोर डाटा व बैकअप कभी भी नष्ट या हैक नहीं हो सकेगा।

सीईएल के सीएमडी चेतन प्रकाश जैन ने बताया कि ग्रीन डेटा सेंटर दो साल में बनाने का लक्ष्य है। पांच मंजिल की इमारत में प्रत्येक फ्लोर पर डाटा स्टोर करने के लिए 200 हाइ-डेंसिटी रैक बनाई जाएंगी। यह सेंटर स्मार्ट कूलिंग, रिफ्लेक्टिव रूफिंग, वर्षा जल संचयन और मल्टी-आइएसपी सपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त होगा और इसकी कुल क्षमता 30 मेगावाट है। जिसे 40 जीबीपीएस कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सीईएल) एक मिनी रत्न सीपीएसई है, जो भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह ग्रीन डेटा सेंटर को ऊर्जा की खपत कम करने वाला, पूरी तरह सुरक्षित और भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ईएसडीएस के साथ साझेदारी के माध्यम से सीईएल आधुनिक क्लाउड और डेटा सेंटर को टेक्नोलाजी के साथ जोड़ रहा है। ईएसडीएस के पेटेंट तकनीक और सेवाएं इस केंद्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएंगी।

डाटा की क्षमता के अनुसार आवंटित होगी रैक : सीईएल के विशेषज्ञों के मुताबिक डाटा की क्षमता के मुताबिक उपभोक्ता को डाटा सेंटर में रैक उपलब्ध कराई जाएगी।

एक ही रैक में दो या इससे अधिक लोगों का डाटा भी सुरक्षित किया जा सकता है। यदि किसी कंपनी या औद्योगिक इकाई का डाटा अधिक है तो उन्हें अलग से रैक उपलब्ध कराई जा सकती है। इसमें वह अपने डाटा को कभी भी डाउनलोड व अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए किसी भी संस्था, व्यक्ति या कंपनी को अपना अकाउंट डाटा सेंटर में खुलवाना होगा। इसके बाद मिले यूजर आइडी और पासवर्ड से ही डाटा देखा जा सकेगा।

सौ करोड़ का प्रक्षिप्त होगा कारोबार : डाटा सेंटर के निर्माण में करीब एक हजार करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है।

इस डाटा सेंटर से सीईएल को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। उम्मीद है कि इससे करीब 10 करोड़ रुपये का सीईएल को प्रतिवर्ष मुनाफा होगा।

मुख्यमंत्री ने जीडीए के 'पहल' पोर्टल का किया विधिवत शुभारंभ

जासं, गाजियाबाद : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन में जीडीए के 'पहल' (पब्लिक एक्सेस फार हाउसिंग एंड प्रोपर्टी एलाटमेंट लागिन) पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। पोर्टल पर आवंटियों को प्राधिकरण की समस्त संपत्तियों की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस पर अभी तक करीब 150 करोड़ से अधिक का राजस्व मिल चुका है। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पहल पोर्टल को नागरिक हित को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। इसके शुरू होने के बाद अभी तक एक लाख 40 हजार से अधिक आवंटियों के लिए इसमें सुविधा

जीडीए की ओर से शुरू किया गया पहल पोर्टल का लोगो ● सौ. जीडीए

दी जा रही है। इसके माध्यम से संपत्ति का भुगतान, लेजर रिपोर्ट और किस्तों का पुनर्निधारण सभी उपलब्ध है। पोर्टल के माध्यम से देश के किसी भी हिस्सों के आवंटी अपने निकटतम बैंक शाखाओं के माध्यम से किस्तों का भुगतान कर सकते हैं। अभी तक 161.22 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके माध्यम से नाम संशोधन के 97 में 83 प्रकरणों में जीडीए की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है।